राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम)

दिव्यता जोशी[1], अंजली चुनेरा[2] और प्रियजोय कर[3]
[1]पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब
[2]जी बी पी यू ए टी, पंतनगर
[3]भा.कु.अनु.प. भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, लुधियाना
संवाददाता ई–मेलः divyatajoshi01@gmail-com

बाजार में विखंडन, बहु–स्तरीय शुल्क और कई हितधारकों के कारण देश में किसानों के लिए कृषि विपणन हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2016 में व्यापार से इन बाधाओं को दूर करने के लिए ई–नाम योजना का शुभारंभ किया गया था। यह 'वन नेशन, वन मार्केट' के तहत एपीएमसी मंडियों को एकीकृत करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है। कोविड–19 महामारी के दौरान, थोक मंडियों में भीड़ को कम करने के लिए सरकार ने पोर्टल में नई सुविधाएँ शुरू कीं। ई–प्लेटफॉर्म पर 150 से अधिक फसलों का विपणन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न कृषि और बागवानी फसलें शामिल हैं। इस योजना का किसानों, व्यापारियों, खरीदारों, निर्यातकों और प्रोसेसर के लिए अत्यधिक प्रभाव है। एकमात्र चिंता राज्यों में इसकी उथली पहुंच है क्योंकि राज्यों को इस योजना को सक्षम करने के लिए कुछ पूर्व–आवश्यकताओं का पालन करना होगा। इसके अलावा, सरकार को इस योजना में अधिक से अधिक किसानों को शामिल करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि देश के कृषि विपणन ढांचे को परिवर्तित किया जा सके और हितधारकों की आजीविका को सुरक्षित किया जा सके।

परिचय

राज्यों के भीतर भी बाजार का विखंडन, कृषि–उपज के मुक्त प्रवाह में बाधा, कई हितधारकों की उपस्थिति, कई मंडी शुल्क और नियम और अलग–अलग कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के नियम और अधिनियम, कृषि विपणन की प्रमुख चुनौती रही है। जिसके परिणामस्वरूप किसान उत्पादकों के लाभ बिना उपभोक्ता के लिए कीमतों में वृद्धि प्रतीत होती है। इस मुद्दे को दूर करने के लिए और देश भर में एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई–नाम) 14 अप्रैल, 2016 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के समर्थन से लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ. ए.सी.) के माध्यम से शुरू की गई थी। ई–नाम कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार में एपीएमसी के तहत मौजूदा मंडियों को एकीकृत करने के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। पोर्टल सभी एपीएमसी संबंधित जानकारी और सेवाएं जैसे कि तात्कालिक कीमतें, सभी खरीद और बिक्री के विकल्प, वैकल्पिक व्यापार प्रस्ताव और अन्य सेवाओं के लिए प्रतिक्रिया एक सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में प्रदान करता है । यह डिजिटल प्लेटफॉर्म उपज की गुणवत्ता के आधार पर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उनके बेहतर कीमत की खोज की सुविधा देता है। यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करने में मदद करता है और कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देता है। ऑनलाइन बाजार भी लेनदेन की लागत को कम करने में मदद करता है, हालांकि वास्तविक कृषि व्यापार मंडियों के माध्यम से होता है।

ई–नाम का महत्व

अपनी स्थापना के बाद से, ई–नाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बाजारों में एकरूपता उत्पन्न करने और एकीकृत बाजारों में उत्पादकों को सुव्यवस्थित करने के लिए कृषि विपणन में चुनौतियों का सामना कर रहा है। दूसरे चरण के अंत में (15 मई तक), ई–नाम के अंतर्गत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पहले चरण में एकीकृत 585 मंडियों में 415 मंडियां जोड़ कर 1000 थोक मंडियों को शामिल किया है।

ई–नाम किसानों, व्यापारियों, खरीदारों, प्रोसेसर और अन्य हितधारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यह उपज बेचने के लिए व्यापक बाजार विकल्पों का वादा करके किसानों के लिए लाभ के अवसर प्रदान करता है। यह द्वितीयक व्यापार के लिए बड़े

राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। यह उपभोक्ताओं, प्रोसेसर और निर्यातकों को स्थानीय मंडी दर में प्रत्यक्ष भागीदारी देता है, गुणवत्ता मानकों और गुणवत्ता परीक्षण के सामंजस्य के प्रावधान के साथ मध्यवर्ती लागत को कम करता है। अब तक 69 वस्तुओं और 1,41,776 व्यापारियों, 82,366 कमीशन एजेंटों, 1612 एफपीओ के लिए व्यापार मापदंड निर्धारित किए गए हैं और विभिन्न राज्यों के 16.9 मिलियन किसान इस मंच से जुड़े हैं। मंडी के पास मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जैसी अन्य सुविधाएं भी किसानों तक आसानी से पहुंचाई जा रही हैं।

देश भर में , कोविड–19 महामारी की स्थिति में तालाबंदी के दौरान, किसान उत्पादक बाजार की उपलब्धता की कमी के कारण अपनी उपज को डंप करने के लिए मजबूर थे। इस स्थिति से उबरने के लिए और किसानों को आसान बाजार सुलभता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ई–नाम पोर्टल पर नई सुविधाएँ शुरू कीं, जिससे किसान मंडियों में किसी भी तरह की भीड़ से बचने के लिए अपनी उपज सीधे चयनित गोदामों को बेच सकें। इसके अलावा, किसानों और व्यापारियों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का गठन किया गया है। इस मंच पर 150 से अधिक कृषि उपज का कारोबार किया जा रहा है, जिसमें खाद्यान्न, दालें, तिलहन, बागवानी उत्पाद और रेशा आदि शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक बाजार किसानों को एपीएमसी मंडियों में दूरस्थ बोली लगाने और परेशानी मुक्त ई–भुगतान के तरीकों का उपयोग करने की सुविधा देता है। इसी के साथ ही सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी) और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (एसडब्ल्यूसी) के साथ ई–नाम, मंडियों के सहयोग से किसानों को बेहतर भंडारण सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी, जो किसान को उपज के असफल होने के जोखिम और अतिरिक्त बोझ को कम करेगा।

मुद्दे

ई–नाम का जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव है लेकिन कुछ खामियां भी हैं जैसेः

1. कई राज्यों ने अभी तक इस योजना का विकल्प नहीं चुना है क्योंकि योजना के तहत सहायता के लिए पात्र होने के लिए पूर्व–आवश्यकताएं हैं। राज्य में कुछ के पास ई–नाम के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की कमी है। यह बुनियादी संरचना में महत्वपूर्ण सुधार है, जैसे राज्य भर में एक एकल लाइसेंस, केवल एक स्तर पर बाजार शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर नीलामी।

2. योजना की पहुंच राज्यों में कम है। भारत में 700 से अधिक जिलों में से केवल 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 69 जिले आकांक्षात्मक हैं। ई–नाम के साथ आगे के जिलों को जोड़ने के लिए राज्यों को योजना के लिए आवश्यक पूर्व–आवश्यकताएँ सुनिश्चित करना है।

3. एपीएमसी के कार्य में पारदर्शिता चिंता का विषय है। सुधार केवल एपीएमसी के नियमों और विनियमों के उचित और अस्पष्ट प्रावधानों के साथ होगा। विपणन समिति को राज्य में योजना के समुचित कार्य को सुनिश्चित करना चाहिए।

4. देश के लगभग 16.7 मिलियन किसान ई–नाम में पंजीकृत हैं। योजना की उथली पहुंच चिंता का विषय है। इसके अलावा, हितधारकों को इलेक्ट्रॉनिक बाजार में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए।

निष्कर्ष

कृषि उपज का विपणन हमेशा देश के किसानों के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक रहा है। ई–नाम की स्थापना राष्ट्रव्यापी बाजार को एकीकृत करने और उपभोक्ता को लागत कम करने और किसानों के लिए कीमतों को कम करने के लिए की गई थी। ई–नाम किसानों को सीधे गोदामों के माध्यम से अपनी उपज बेचने की अनुमति देकर बाजार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। अब कृषि विपणन की संरचना को बदलने के लिए अधिक से अधिक किसानों को इस इलेक्ट्रॉनिक बाजार से जोड़ने की आवश्यकता है और अंततः किसानों को उनकी उपज के लिए एक पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करना है ताकि उनके जीवन का उत्थान हो सके।

संदर्भः

https://www.enam.gov.in/web/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/e-nam-platform-onboards-1000-mandis-in-21-states/uts-centre/articleshow/75764965.cms